Consumer Movement in Rural Areas

1712. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any plan of action to take the consumer movement to the rural areas for the benefit of the people;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) what effective measures are being taken by Government in this respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (d) Governnment has taken a number of measures to increase consumer consciousness amongst the people in rural areas. Such measures include preparation of audio-visual materials, printed literature in the form of booklets brochures, posters, postcard size materials, etc. in the field of consumer protection. The Government is also publishing a quarterly journal, 'Upbhokta Jagaran', which disseminates useful information to the consumers. The Printed materials are made available free of cost to the consumer organisations for spreading the message of consumer protection amongst all sections of the society including the rural people. Besides, financial assistance is also provided to State Governments/UT Administrations for arranging regional/State level seminars and workshops for involving the people at the grass-root level in the programmes of consumer protection. Voluntry organisations are being encouraged to spread consumer awareness in rural areas.

Duplicate Electric Goods

1713. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that non-ISI marked and duplicate electric goods are sold by retailers throughout the country resulting in electric shocks and damage to electric gadgets;

(b) if so, what action Government have taken or propose to take so that only ISI marked electric goods are marketed in the country;

(c) whether Government have taken any action in this regard during the last two years; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) There are reports about the electric goods which the under mandatory BIS certification, being sold without ISI mark in some parts of the country.

(b) to (d) The enforcement of the quality control orders issued under the Essential Commodities act, 1955 lies with the States/UTs. The Government of India has been urging the States/UTs from time to time to ensure effective enforcement of quality control orders. Some of the actions taken in the recent past are as under:—

(a) 3 GLS lamps manufacturing units were raided in Delhi and large quantity of GLS lamps seized.

(b) Electric switches and sockets seized by the Govt. of Tamil Nadu from traders in Madras and Madurai.

(c) Electric irons and immersion rods seized by the Govt. of Haryana in Ambala.

(d) 1727 seizures made by the Govt. of Gujarat covering various ellectrical items covered under relevant quality control orders.

तोल और माप नियमों की समीक्षा

1714. **श्री अजीत जोगी :** क्या **नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले-बाजार की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए तोल और माप नियमों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति सहित विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है,

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे है कि कानून के तकनीकी पहलू और प्रवर्तन तंत्र प्रौद्योगिकी के विकास के साथ समान गति से आगे बढ़े, और

(घ) माप पद्धति के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रवर्तन तंत्र, जनता, उद्योग और व्यापार को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि अधिनियम का कार्यान्वयन प्रभावी ढग से हो सके तथा इसे उपभोक्ताओं के लिए और अधिक लाभदायक बनाये जा सके ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सावजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) वाट तथा माप नियमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है, उन्हें संशोधित किया जाता है ।

(ख) स्थायी समिति ने हाल ही में बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुए) नियम, 1977 के कुछ उपबधों में संशोधन करने हेतु सिफारिश की है।

(ग) और (घ) प्रवर्तन कर्मचारियों को इस विषय में उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, वे समय-समय पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए जाते है। लोगों इत्यादि को शिक्षित करने के लिए, केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर व्यापक प्रचार हेतु प्रचार सामग्री तैयार की जाती है। राज्य सरकारें कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर आयोजित की जाने वाली "प्रदर्शनियों" मे जनता को कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए अपने स्टॉल लगाती है।

Strategy of BIS to Boost Quality Movement

1715. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether the Bureau of Indian Standards (BIS) has shifted its strategy from a target oriented approach to a need based one to boost the quality movement in the country in view of the economic liberalisation ;

(b) if so, the broad features of the new plan for quality control ;

(c) whether the BIS has also tied up with a leading quality systems certification agency in Germany (DQS) and a subsidiary of DIN the German standards body, for bilaterial co-operation in certification of quality systems ; and

(d) how far this tie-up with German agency will help in the Indian products having easy access to the whole of Europe?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) BIS activities relating to standardization and quality control are always need-based. Recently, new orientation has been given to the selection of subjects for formulation of Indian Standards with the objective of avoiding unnecessary proliferation of standards.

(c) Yes, Sir.

(d) There have been demands from Indian industry to get quality system certificate from leading European certification bodies in addition to BIS so as to maintain a competitive edge in European Union and other developed economies. To fulfil this demand a Memorandum of Understanding has been signed with DQS, Germany.

सुपर बाजार में कार्यरत महिला कमचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

1716. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुपर बाजार की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत महिला कर्मचारियों से उनके अधिकारियों और सहयोगियों द्वारा दुर्व्यवहार और परेशान किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला कर्मचारियो के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें परेशान करने के शाखा-वार कितने मामले हुए और सुपर बाजार के महाप्रबंधक के पास ऐसी कितनी शिकायतें दर्ज हुई;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अभ्यावेदनों और शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) सुपर बाजार की महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा उन्हें तंग करने के बारे मे दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो यशवन्त पैलेस शाखा तथा क्षेत्रीय वितरण केन्द्र त्रिलोकपुरी से संबंधित हैं। दोनों मामलों में जांच की गई थी और दोषी कर्मचारियो को चेतावनी दी गई थी। कार्यबार, सुपर बाजार में पुरुष तथा महिला कर्मचारी समान है और महिला कर्मचारियों के प्रति पुरुष कर्मचारियो द्वारा सामान्य शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी महिला कर्मचारी के प्रति दुर्व्यवहार का कोई मामला सुपर बाजार की जानकारी में आता है, तो दोषी पाए गए पुरुष कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

Assistance from Consumer Welfare Fund to Gujarat

1717. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTON be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat has requested for assistance from the Consumer Welfare Fund during the years 1993-94 and so far in 1994-95 ;

(b) if so, the details thereof ;